(iv) Self-employment is promoted through the following:—

(a) Allotment of vending stalls, kiosks an shops by some State Govts ./UTs;

(b) Loans from Nationalised Banks at concessional Rates of Interest;

(c) Preference in allotment of Public Telephone booths;

(d) Reservation in distribution of Petrol Pumps, Kerosence Depots etc.

(7) *Scheme of Assistance to disabled for purchase/fitting of Aids/Ap pliances*

The main objective of the scheme is to assist needy physically handicapped persons in procurring durable, sophisticated the scientifically manufactured aids and appliances that promote their physical, social and psychological rehabilitation. The scheme is implemented through Centres run by the Companies, registered under Companies Act, registered Societies, trusts or any other institutions recognised by the Ministry of Welfare. Both governmental and non-governmental agencies are thus engaged for the implementation of the scheme.

Under the scheme, aids and appliances upto value of Rs. 3600/- are distributed to the disabled persons free of cost if their monthly income is upto Rs. 1200/-and at 50% or the cost if the income is between Rs. 1201 to Rs. 2500/-.

(8) Government of India have recently enacted "The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995". The Act provides prevention and early detection of disabilities, education, employment non-discrimination etc. for disabled persons including mentally handicapped persons.

(9) National Handicapped Finance & Development Corpn. is being set up to provide an additional channel of finance at concessional rates to enable the handicapped persons to take up self-employment projects.

Lock-out in Patriot Newspaper

778. SHRI RAM NATH KOV1ND: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether newspaper 'Patriot' is under lock-out;

(b) if so, the effective date of such lock-out with reasons therefor;

(c) whether such lock-out exercise in the 'Patriot' newspaper has been activised several times by management in past too;

(d) if so, the details of such lock-out in chronological order since establishment of the organisation;

(e) whether Government propose to ask existing group of newspapers of the country to take over management of 'Patriot' newspaper to resolve the crisis of repeated lock-out;

(f) if so, the details thereof; and

(g) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) Yes, Sir, w.e.f. 14.6.1996, the newspaper 'Patriot' is under lock-out due to financial crisis.

(c) As per information available, no lock-out has been declared by the management in the last two years.

(d) In view of the above, question does not arise.

(e) No such proposal is under consideration.

(f) and (g) Does not arise in view of (e) above.

Modernising rescue services in coal mines

779. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the rescue services in coal mines have not been modernised so far;

(0) it so, how do they compare with those in the developed countries;

(c) the measures proposed for modernisation; and

(d) by when the modernisation programme will be completed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (d) Modernisation of rescue services in coal mines, undertaken in accordance with the modernisation plan drawn up in this regard, is expected to be completed by the end of 1998. The plan envisaging construction of new rescue stations and rescue rooms in different coalfields, provision of state-of-the-art rescue apparatus and equipment and also upgradation of-the training standards for rescue brigades etc., compares favourably with those provided in the developed countries.

लघु उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि किया जाना

780. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार लघु औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश की वर्तमान अधिकतम सीमा कितनी है और सरकार ने इसे किस सीमा तक बढ़ाना निर्धारित किया है;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में उल्लिखित मदों की वर्तमान संख्या को कम करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विनिर्माण के लिए आरक्षित मद-सूची से बाहर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) इस समय लघु उद्योग एकक के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख रु० है। अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों/निर्यातोन्मुख लघु उद्योग एककों के लिए यह सीमा 75 लाख रु० है। सरकार, वर्तमान पूंजी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है।

(ग) से (ङ) इस समय, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की संख्या 836 है। लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

देश में बेरोजगारी

781. **श्री रामजीलाल:**
श्री जगन्नाथ सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुशल और अकुशल शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं; और

(ख) इस बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है और वह सभी बेरोजगार व्यक्तियों को कब तक रोजगार उपलब्ध करा देगी?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) 31.12.1989 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत कुशल/अर्धकुशल एवं अकुशल रोजगार चाहने वाले यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हो, की संख्या क्रमशः 11.8 लाख तथा 49.3 लाख थी।

(ख) यद्यपि नई आर्थिक नीति के 1991 के प्रारम्भ से रोजगार चाहने वालों की संख्या में कोई दीर्घकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी है। सरकार ने रोजगार सृजन को अपनी विकास योजनाओं हेतु किये जाने वाले प्रयासों के केन्द्र में रखा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च रोजगार संभाव्यता वाले सैक्टरों तथा सब-सैक्टरों यथा, कृषि, कृषि तथा ग्राम्य उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र, शहरी अनौपचारिक तथा सेवा क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, पहले से चालू योजनाओं, यथा, आई आर डी पी, जे आर वाई तथा एन आर वाई के साथ-साथ नई रोजगार सृजन योजनाएं यथा, रोजगार आश्वासन योजना (इ ए एस), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर